

मुकदमों का विवरण

पलावी

बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

(2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 642) सितंबर 1, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: याचिकाकर्ता-विदेशी राष्ट्रीय, स्नातकोत्तर चिकित्सा सीट के लिए उम्मीदवारी की अस्वीकृति को चुनौती देती है जब उसे एन. ई. ई. टी. मुख्य परीक्षा में प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी, जिसमें उसने नकली दौर में भाग लिया था और उसे एम्स में बाल रोग में पी. जी. आवंटित किया गया था, हालांकि, परामर्श के पहले दौर से ठीक पहले उसे सूचित किया गया था कि उसे एक भारतीय नागरिक के रूप में माना जाएगा न कि एक विदेशी नागरिक के रूप में।

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान-चिकित्सा शिक्षा-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश-लिखित परीक्षा में भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड-ओ. सी. आई. कार्ड रखने वाले विदेशी नागरिक ने मॉक राउंड में भाग लिया और एम्स में पीडियाट्रिक्स में पी. जी. से बाहर हो गए-हालांकि, परामर्श के पहले दौर से ठीक पहले, अधिसूचना के आधार पर विदेशी नागरिक से भारतीय नागरिक का दर्जा बदलकर पीजी मेडिकल सीट के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया, एन. ई. ई. टी. परीक्षा में बैठने के लिए भारतीय नागरिकों के साथ उनकी समानता के संबंध में ओ. सी. आई. कार्ड धारकों को दिए गए विशेषाधिकारों को वापस ले लिया गया-वैधता:

आयोजित किया गया: ओ. सी. आई. कार्ड धारक के लाभ का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता से इनकार नहीं किया जा सकता है-उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करना कानून में समर्थित नहीं है-अधिसूचना दिनांक 04.03.2021 मनमाने ढंग से संचालित की गई क्योंकि यह अर्जित अधिकारों को नहीं बचाने में दिमाग का उपयोग न करने का संकेत देती है; और अधिसूचना के खंड 4 (ii) के परंतुक के आवेदन को प्राप्त करने के लिए मांगे गए उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं माना गया था-जब परंतुक किए गए अधिकार को वापस ले लिया गया था और बदल दिया गया था, तो इस तरह के परिवर्तन की प्रक्रिया में, इसे इस तरह की वापसी या संशोधन के उद्देश्य के लिए दिमाग के अनुप्रयोग, संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए।

943 944

[2023] 11 एस सी आर।

और इस तरह का कोई भी निर्णय मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए-अधिसूचना को दिमाग का उपयोग न करने की बुराई से बचाया गया और वास्तव में पूर्वव्यापी था-इन परिस्थितियों में यह माना गया था कि केवल वे व्यक्ति जिन्होंने 04.03.2021 के बाद ओसीआई कार्ड प्राप्त किए थे, उन्हें अधिसूचना के संदर्भ में अयोग्य घोषित कर दिया गया था-इस प्रकार, एम्स और सभी भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा पीजी मेडिकल सीटों के लिए शेष परामर्श दौर में याची पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करना-नागरिकता अधिनियम, 1955 -एस. 7 ए से डी. [पारस 14-17]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

अनुष्का रेंगुन्थवार और ओआरएस. वी.भारत संघ और अन्य। 2023 एससीसी
ऑनलाइन एससी 102-पर भरोसा किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 642।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

रूप:

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिवेंद्र सिंह, बिक्रम द्विवेदी, राघव गुप्ता, पुनीत सिंघल, अभिजात ओबेरॉय, डॉ. मुकल नाथ वर्मा, घारोटे अनुराग ए, अधिवक्तागण याची के लिए।

अतुल कुमार, सुश्री स्वीटी सिंह, सुश्री अर्चना कुमारी, राहुल पांडे, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, परांजय त्रिपाठी, सुश्री रुचि कोहली, अमेय विक्रम थानवी, भुवन कपूर, अमन शर्मा, सुश्री शगुन ठाकुर, प्रवीण गौतम, जी. एस. मक्कड़, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

1. याची ने 945 की उम्मीदवारी की अस्वीकृति से व्यथित संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत की मांग करते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है

पलावी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 946 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

स्नातकोत्तर चिकित्सा सीट के लिए; लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने और एन. ई. ई. टी. (पी. जी.) और आई. एन. आई.-सी. ई. टी./2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से "एन.

ई. ई. टी". कहा जाता है) के लिए परिणाम घोषित किए जाने के बाद प्रत्यर्थी ने उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया।

2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), एन. ई. ई. टी. परीक्षा/परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी, ने 07.03.2023 पर एन. ई. ई. टी. प्रक्रिया के लिए विवरण पत्रिका प्रकाशित करके योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। याची ने आवेदन किया और उसे परीक्षा प्रवेश पत्र on 01.05.2023 जारी किया गया। उन्होंने 07.05.2023 पर एन. ई. ई. टी. परीक्षा में भाग लिया और उपस्थित हुई। याची के पास एक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड है (जिसे बाद में "ओसीआई कार्ड धारक" कहा जाता है)। वह एक अमेरिकी नागरिक हैं और उनका जन्म 22.02.1999 पर हुआ था।

3. उत्तरदाताओं द्वारा प्रकाशित विवरण पत्रिका ने पात्रता शर्तों को निर्धारित किया जो इंगित करती हैं कि उम्मीदवार के पास चिकित्सा या दंत चिकित्सा की डिग्री होनी चाहिए और 12 महीने के प्रशिक्षण की आवश्यक अवधि पूरी होनी चाहिए और प्रतिशत में ग्रेडिंग का मूल्य निर्धारित करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों से ग्रेडिंग प्रणाली का प्रमाण पत्र होना चाहिए और एमबीबीएस/बीडीएस व्यावसायिक परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत या समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा, विदेशी नागरिकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आवश्यक माना गया था। यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाना था। ओ. सी. आई. उम्मीदवारों के लिए शर्त और भारतीय नागरिकों के साथ-साथ प्रायोजित और विदेशी नागरिकों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रासंगिक आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

“प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ. सी. आई.): भारत के प्रवासी नागरिक उम्मीदवार विदेशी राष्ट्रीय सीटों के खिलाफ आवेदन कर सकते हैं। ओ. सी. आई

उम्मीदवारों को एन. ओ. सी. प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि ओ. सी. आई. कार्ड की स्कैन प्रति उल्लिखित तिथि (तारीखों) पर या उससे पहले अपलोड करनी चाहिए।

प्रॉस्पेक्टस भाग-ए के महत्वपूर्ण तिथियों खंड में। खंड **V:** विभिन्न आई. एन. आई. के जुलाई **2023** सत्र के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटें

जुलाई 2023 सत्र के लिए भाग लेने वाले आई. एन. आई. में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटें दो प्रकार की हैं।

1. सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध सीटें (प्रायोजित और विदेशी राष्ट्रीय सीटों को छोड़कर)

विभिन्न आई. एन. आई. के जुलाई 2023 सत्र के लिए भाग लेने वाले आई. एन. आई. में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की एक समेकित सूची संबंधित आई. एन. आई. से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के आधार पर परीक्षा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली द्वारा तैयार और प्रकाशित की जाएगी। विभिन्न आई. एन. आई. से प्राप्त आई. एन. आई.-वार सूची

आई. एन. आई.-सी. ई. टी. पोर्टल के उपलब्ध सीटें टैब से उपलब्ध होगी। ये सूचियाँ संबंधित आई. एन. आई. के निर्णय के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं और परीक्षा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अद्यतन की जाएंगी। उपलब्ध सीटों की सूची परिणाम घोषित होने के बाद नहीं बदली जाएगी। जुलाई 2023 सत्र के लिए सीट आवंटन (आईएनआई-वार और विशेषता-वार) के लिए उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों की अद्यतन समेकित सूची परिणाम की घोषणा से पहले प्रकाशित की जाएगी।

2. प्रायोजित और विदेशी राष्ट्रीय के लिए उपलब्ध सीटें

आई. एन. आई.-वार और विशेषज्ञता-वार उपलब्ध सीटों की सूची

प्रायोजित और विदेशी नागरिक इसके माध्यम से सुलभ होंगे।

"महत्वपूर्ण तिथियों" टैब में उल्लिखित के अनुसार "आवेदन पूरा होने" पर या उससे पहले उपलब्ध सीटें टैब।

4. याचिकाकर्ता के आवेदन ने उन्हें ओ. सी. आई. उम्मीदवार के रूप में सूचीबद्ध किया, और वह उस क्षमता में परीक्षा में उपस्थित हुई; 13.05.2023 पर घोषित परिणामों से पता चला कि उन्होंने 96.73 प्रतिशत प्राप्त किया था, और उनकी समग्र रैंक 1902 थी। यह दावा किया जाता है कि इस सूची ने उन्हें ओ. सी. आई. श्रेणी में भी मान्यता दी। उनके रोल नंबर का उल्लेख 13.05.2023 पर प्रकाशित उम्मीदवारों की अस्थायी रूप से योग्य विज्ञापन सूची में किया गया था।

5. दिनांक 25.05.2023 1 के संचार ने संस्थान और विषयवार द्वारा ऑनलाइन सीट आवंटन के पहले और दूसरे दौर के लिए जानकारी प्रदान की। एम्स ने 10.06.2023 पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सीट आवंटन (सूचना संख्या 97/2023) के लिए एक अनुसूची जारी की। उसी दिन, याची को सूचित किया गया कि उसे एक विदेशी नागरिक के रूप में माना जाएगा

1 नहीं। एफ. एम्स/एकजाम. एस. ई. सी./4-5/(आई. एन. आई.-सी. ई. टी.-पी. जी.-जून-2023)/2023।

पलावी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 948

947

उसने ओ. सी. आई. उम्मीदवार 2 के रूप में अपनी स्थिति का खुलासा किया था। उन्हें बताया गया कि आवेदन प्रक्रिया का नकली दौर 11.06.2023 पर शुरू हो गया है और 13.06.2023 पर समाप्त होगा।

6. 15.06.2023 पर, ऑनलाइन मॉक राउंड का परिणाम घोषित किया गया था। याची को एम्स में 'बाल रोग' अनुशासन आवंटित किया गया था। यह 15.06.2023 पर प्रकाशित पहले दौर से पहले ऑनलाइन नकली सीट आवंटन की घोषणा से स्पष्ट है। इन घटनाक्रमों के आलोक में, अचानक 19.06.2023 पर, उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें अब ओ. सी. आई.

उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें "भारतीय राष्ट्रीय" की श्रेणी में माना जाएगा। यह एक सार्वजनिक सूचना संख्या 119/2023 के आधार पर प्रकाशित किया गया था। याची द्वारा 19.06.2023 पर ही उस प्रभाव को एक ई-मेल संचार प्राप्त किया गया था।

7. जैसे ही प्रथम दौर की परामर्श प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, याची को सूचित किया गया और आरोप लगाया गया कि उसके पास भारतीय नागरिक का दर्जा चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उसने विरोध में किया और प्रथम दौर की परामर्श प्रक्रिया में भाग लिया। इसलिए, उन्होंने इसके तुरंत बाद, आईडी1 पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने और उनकी ओर से कोई त्रुटि या गलती नहीं होने के बावजूद, उनकी स्थिति में बदलाव ने पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश की संभावनाओं को काफी कम कर दिया था। उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि संभवतः केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.03.2021 के आधार पर स्थिति में परिवर्तन अनुचित है क्योंकि उन्होंने इस शब्द को सभी अर्थों में जला दिया है या अपने विकल्पों को बंद कर दिया है।

8. यह तर्क दिया जाता है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, वर्ष 2005 से और विशेष रूप से उनके उच्च शिक्षा प्रक्षेपवक्र ने उन्हें ओ. सी. आई. कार्ड वाले विदेशी नागरिक के रूप में प्रवेश के लिए योग्य बना दिया। याची को भारतीय नागरिक मानने का एम्स का स्पष्ट निर्णय अनुचित और मनमाना है।

9. इसका प्रतिवाद श्री विनय नवारे, एल. डी. ने किया है। याची की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस रुख में बदलाव का आधार गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.03.2021 3 है, जिसका शीर्षक है (एन. ई. ई. टी. में प्रवेश के मामले में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता)

2 (ओ. सी. आई. कार्ड रखने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड दिनांकित 10.06.2023) था।³ नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी के तहत जारी किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

एक अपवाद का संकेत दिया कि ओ. सी. आई. कार्ड धारक विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए अयोग्य हैं।

10. श्री नवारे ने तर्क दिया कि अधिसूचना का विषय था

अनुष्का रेंगुथवार और अन्य मामलों में इस न्यायालय का फैसला। V. भारत संघ और

ओआरएस 4. यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार उन मामलों के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है जो उसने 04.03.2021 पर किए थे, जिनके लिए गणना या प्रावधान किया गया था। फिर भी उसी समय, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया

कि उस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है और इसके आवेदन पर प्रतीत होने के बावजूद इसमें पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का एक तत्व है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ओ. सी. आई. कार्ड धारक की स्थिति का मतलब है कि याची जैसे व्यक्तियों को भारत के विदेशी नागरिकों के रूप में माना जाता है और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए से 7 डी (इसके बाद "1955 अधिनियम") ने उनके पंजीकरण और रद्द करने की प्रक्रिया को इस बात को ध्यान में रखते हुए लागू किया कि पहले की अधिसूचना दिनांक

11.04.2005, 05.01.2007 और 05.01.2009 ने ऐसे ओ. सी. आई. कार्डधारकों को भारत में शैक्षणिक संस्थानों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाया था और राज्य उन्हें अचानक इस तरह के लाभ से वंचित नहीं कर सकता था। इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायालय ने, इसलिए, घोषणा की कि अधिसूचना का संचालन जो पहले की अधिसूचना और खंड 4 (ii) के अधिक्रमण के लिए प्रदान करता है और इसके परंतुक और स्पष्टीकरण केवल ओ. सी. आई. कार्ड धारक के संबंध में संभावित रूप से काम कर सकते हैं जिन्होंने परिणामस्वरूप प्रवेश प्राप्त किया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में ओ. सी. आई. कार्ड याची को उस तारीख से पहले, यानी 02.11.2015 पर जारी किया गया था।

11. विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार ने दिनांकित अधिसूचना पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि अनुष्का (ऊपर) में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि इसका संभावित प्रभाव था। इसका मतलब था कि बाद के सभी वर्षों के लिए, यानी 2021-22 के बाद, अधिसूचना लागू थी। यह तर्क दिया गया था कि किसी भी स्थिति में चूंकि याची का जन्म 04.03.2021 से बहुत पहले हुआ था, इसलिए अधिसूचना (04.03.2021) का आवेदन निर्णय की तारीख यानी 03.02.2023 से प्रभावी तरीके से संचालित होता है।

12. एम्स ने याची के साथ यह खुलासा नहीं करने के लिए गलती की कि वह 04.03.2021 से पहले एक ओसीआई कार्ड धारक थी, जिसे अनुष्का (उपरोक्त) में घोषित कानून के संबंध में एक विशेष कारक के रूप में देखा जाना था।

4 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 102।

पलावी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 950 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

949

विश्लेषण और निष्कर्ष

13. अनुष्का (ऊपर) के फैसले में विदेशी अधिनियम, 1946 और नागरिकता अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में स्थिति का विश्लेषण किया गया, विशेष रूप से धारा 7 ए से 7 डी और विचाराधीन अधिसूचना से पहले, यानी दिनांक 11.04.2005, 05.01.2007 और 05.01.2009 जो 1955 के अधिनियम की धारा 7 बी के तहत भी जारी किए गए थे। प्रत्येक अधिसूचना में घोषणा की गई थी कि ओ. सी. आई. कार्ड धारकों के साथ गैर-निवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) और भारतीय नागरिकों के बराबर व्यवहार किया जाना चाहिए और

उन्हें दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसमें अखिल भारतीय पूर्व-चिकित्सा परीक्षा और ऐसी सभी अन्य परीक्षाओं में भाग लेना शामिल है ताकि वे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र हो सकें।

04.03.2021 दिनांकित अधिसूचना में विशेष रूप से इस प्रकार कहा गया है:

“गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

“एस. ओ. 1050 (ई)-नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7 बी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के स्थान पर 11 अप्रैल, 2005 को आधिकारिक राजपत्र संख्या एस. ओ. 542 (ई) में प्रकाशित किया गया और 5 जनवरी, 2007 को आधिकारिक राजपत्र संख्या एस. ओ. 12 (ई) और 5 जनवरी, 2009 को एस. ओ. 36 (ई) में प्रकाशित पूर्ववर्ती प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना को छोड़कर, -

(4) निम्नलिखित मामलों में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता-

((ii)) अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं जैसे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उन्नत) या ऐसी अन्य परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना ताकि वे केवल किसी भी अनिवासी भारतीय सीट या किसी अतिरिक्त सीट पर प्रवेश के लिए पात्र हो सकें।

बशर्ते कि ओ. सी. आई. कार्डधारक विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित किसी भी सीट पर प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।”

14. इस मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं; निस्संदेह याची को एक विदेशी नागरिक के रूप में माना गया था और एन. ई. ई. टी. मुख्य परीक्षा में ओ. सी. आई. कार्डधारक के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी; उसने काफी उच्च रैंक भी हासिल की थी। उन्होंने आवंटन के नकली दौर में भाग लेने की अनुमति दी गई, जिससे यह संकेत मिला कि वह एम्स में बाल रोग में पीजी से बाहर हो जाएंगी और परामर्श के पहले दौर से ठीक पहले उन्हें सूचित किया गया कि उनकी स्थिति अब एक विदेशी नागरिक के रूप में नहीं होगी और उन्हें एक भारतीय नागरिक के रूप में माना जाएगा। 15. अधिसूचना के एक सादे अध्ययन से निस्संदेह यह निष्कर्ष निकलता है कि यह उन पात्रता या विशेषाधिकारों को वापस ले लेता है जो अब तक ओ. सी. आई. कार्ड धारकों को एन. ई. ई. टी. जैसी अखिल भारतीय परीक्षाओं में बैठने के लिए भारतीय नागरिकों के साथ उनकी समानता के संबंध में प्रदान किए गए थे। इसका मतलब यह था कि उस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बाद, यानी 04.03.2021, ऐसे ओसीआई कार्ड धारक किसी भी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते थे "विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित कोई भी सीट" एक अचानक

अधिसूचना थी इन सभी अधिसूचनाओं को पूर्वव्यापी आवेदन के माध्यम से कुछ हद तक नरम कर दिया गया था कि सभी ओसीआई कार्ड धारक जिन्होंने पूर्व-मौजूदा अधिसूचना दिनांक 11.04.2005, 05.01.2007 और 05.01.2009 के आधार पर अपने शैक्षणिक करियर की योजना बनाई थी, उन्हें अनुष्का (उपरोक्त) में निर्णय के संदर्भ में उस विशेषाधिकार के साथ जारी रखने के लिए पात्र माना गया था। अनुष्का (ऊपर) में निर्णय के प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं:

“45. हालाँकि, जिस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वह यह है कि अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट या ऐसी अन्य परीक्षाओं में बैठने के मामले सहित शैक्षणिक समानता के रूप में दिनांकित 11.04.2005 और 05.01.2009 अधिसूचना के माध्यम से दिया गया अधिकार पूरी तरह से बदल दिया गया है ताकि उन्हें प्रवेश के लिए योग्य बनाया जा सके। यद्यपि अधिसूचना पूर्वव्यापी आवेदन को निर्दिष्ट नहीं कर सकती है, लेकिन पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को निरस्त करने का प्रभाव और खंड 4 (ii) में पेश किया गया परंतुक दिनांकित 04.03.2021 'पूर्वव्यापी' अधिसूचना को उस सुनिश्चित अधिकार को छीनने के रूप में 'पूर्वव्यापी' बना देगा, जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों ने अपनी स्थिति में बदलाव किया है और पेशेवर शिक्षा में अपने करियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद के साथ जीवन के प्रक्षेपवक्र को समायोजित किया है।

पलावी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 952 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

951

46. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील उस संदर्भ में तर्क देंगे कि चूंकि अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी की उप-धारा (2) संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार को बाहर नहीं करती है, इसलिए इसे लागू विद्वान जा सकता है और ओ. सी. आई. कार्डधारकों को बाहर करने के लिए अधिसूचना में विचार किए गए इस तरह के भेदभाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू किया जा सकता है और भेदभाव का विरोध केवल तभी किया जा सकता है जब समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है और इस दृष्टिकोण से ओ. सी. आई. कार्डधारक अपने आप में एक वर्ग होने के नाते भारतीय नागरिकों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि दिए गए सीमित वैधानिक अधिकार को बचाने का प्रयास किया जाए। उस हद तक निश्चित रूप से अपनाई गई प्रक्रिया में निष्पक्षता का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसके लिए परिवर्तन किया जाता है और प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विवादित अधिसूचना जारी करने से पहले मन के अनुप्रयोग के लिए जांच की आवश्यकता होती है।

47. जैसा कि उल्लेख किया गया है, दोहरी नागरिकता के अभाव में ओ. सी. आई. कार्डधारकों का अधिकार एक बीच का अधिकार है। जब एक वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था और इस तरह के अधिकार को एक अधिसूचना के माध्यम से वापस लिया जा रहा है, तो वापस लेने

की प्रक्रिया को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है कि की गई कार्रवाई उचित है और इसका उद्देश्य से संबंध है। यह मनमाना नहीं होना चाहिए, बिना आधार के और इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल एक संप्रभु शक्ति होने के कारण परिणामों की परवाह किए बिना नहीं किया जा सकता है। इस पहलू की जांच करने के लिए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा आग्रह की गई दलीलों के अलावा हमने रिट याचिका के साथ आपत्ति बयान पर भी ध्यान दिया है। यद्यपि एक नागरिक की स्थिति और राज्य की संप्रभु शक्ति के संबंध में विस्तृत विवाद का आग्रह किया गया है, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इन याचिकाओं में संप्रभु शक्ति पर सवाल नहीं उठाया गया है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, उस पर आपत्ति है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि शुरू से ही ओ. सी. आई. कार्डधारकों को केवल एन. आर. आई. के साथ समानता प्रदान करने का इरादा था। उस पहलू पर जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख विद्वान गया है, हमने उस लाभ की प्रकृति को देखा है जिसे वर्ष 2005, 2007 और 2009 की अधिसूचनाओं के तहत याचिकाकर्ताओं और इसी तरह रखे गए याचिकाकर्ताओं को दिया गया था। ओ. सी. आई. कार्डधारकों को केवल उन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बराबरी करने के रूप में आगे का विवाद जो एन. आर. आई. के लिए आरक्षित हैं और ओ. सी. आई. कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों के लिए विशेष रूप से आरक्षित किसी भी सीट के खिलाफ प्रवेश के लिए बाहर करने के लिए, पूरे बोर्ड में, यहां तक कि उन व्यक्तियों के लिए भी जो थे

पहले अधिकार दिए जाने पर, यह कहा जाता है कि इसका कारण ऐसे मामलों में भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है जहां राज्य ओ. सी. आई. कार्ड रखने वाले विदेशियों की तुलना में अपने नागरिकों को प्राथमिकता दे सकता है। काउंटर में यह भी कहा गया है कि भारत में चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या बहुत सीमित है और यह भारतीय नागरिकों की आवश्यकता को भी पूरी तरह से पूरा नहीं करती है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी सीटों पर प्रवेश का अधिकार मुख्य रूप से ओ. सी. आई. कार्डधारकों सहित विदेशियों के बजाय भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

48. आपत्ति विवरण में नंगे बयान के अलावा, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए की गई वास्तविक कवायद के संबंध में कोई सामग्री नहीं है कि चयन प्रक्रिया में ओ. सी. आई. कार्डधारकों की भागीदारी ने भारतीय नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया है। इस बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कितने ओ. सी. आई. कार्डधारक चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने के बाद एक सीट प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जिसके द्वारा भारतीय नागरिकों को सीटों से वंचित किया गया था, हालांकि वे समान योग्यता-वार थे।

52. इसलिए यह स्पष्ट है कि वर्ष 2005 में ओ. सी. आई. कार्ड जारी करने का अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य दोहरी नागरिकता की मांग के जवाब में था और इस तरह, दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप में, जिसे मान्यता नहीं दी गई थी, ओ. सी. आई. कार्ड बेनिफिट को बढ़ाया गया था। यदि इस संदर्भ में, पहले याची के विवरण का विश्लेषण किया जाता है, हालांकि याची संख्या 1 को उसके जन्म के तुरंत बाद या अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत प्रदान की गई नागरिकता के पंजीकरण द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प उसके माता-पिता के लिए तत्काल तथ्यों में उपलब्ध था, जब याची संख्या 1 के जन्म के तुरंत बाद ओसीआई कार्ड जारी करने के प्रावधान को सांविधिक रूप से मान्यता दी गई थी और अधिसूचना के तहत शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया था, तो याची संख्या 1 के माता-पिता को वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने या विदेश की नागरिकता का त्याग करने और नागरिकता का पंजीकरण करने का विकल्प चुनने की आवश्यकता थी।

पलावी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 954 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

लाभ प्रदान किया गया था और याची संख्या 1 के लिए उपलब्ध था और पूरे भविष्य की योजना उसी आधार पर बनाई गई थी और यह स्थिति वर्ष 2021 तक जारी रही।

53. इसके अलावा, वर्ष 2021 में जब विवादित अधिसूचना जारी की गई थी, याची संख्या 1 की आयु लगभग 18 वर्ष थी, यानी पूर्ण आयु और भले ही उस स्तर पर, याची को धारा 5 (1) (च) (छ) के तहत प्रदान किए गए भारत की नागरिकता का त्याग करना और मांग करनी थी, ऐसी प्रक्रिया की अवधि उसे भारत में उसके द्वारा चलाए गए पूर्व-विद्यालय चरण से पूरे शिक्षा पाठ्यक्रम के लाभ से वंचित कर देगी और पूर्व-चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए लाभ जो उसके लिए उपलब्ध था, उसे एक ही झटके में मिटा दिया जाएगा। न ही उसे उस देश में कोई विशेष लाभ मिलेगा जहाँ वह पैदा हुई थी। इसलिए उस परिस्थिति में जब किसी संप्रभु राज्य से याची संख्या 1 जैसे व्यक्तियों को अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रदान किए गए अधिकार को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया गया था और भारत के ऐसे प्रवासी नागरिकों द्वारा इसका लाभ उठाने के लिए सभी 'कार्य' किए गए थे और जब यह सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लाभ में परिपक्व होने का चरण था, तो किए गए सभी 'कार्य' को पूर्व अधिसूचना के मुद्दे के साथ पूर्ववत अधिसूचना के मुद्दे के साथ पूर्ववत और अमान्य नहीं किया जाना चाहिए था ताकि उन्हें दिए गए लाभ को भी छीन लिया जा सके।

54. इसलिए, इसके बावजूद, इस तरह के अर्जित अधिकारों को नहीं बचाने वाली विवादित अधिसूचना कार्रवाई में विवेक और मनमानेपन के गैर-अनुप्रयोग का संकेत देगी। आगे ऐसी परिस्थिति में जब कथित उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए अधिक सीटें उपलब्ध कराना था और यह प्रदर्शित किया जाता है कि सीटें खाली रह गई हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए इस तरह की अधिसूचना जारी की गई थी, वह अधिकारों को बचाए बिना और याचिकाकर्ताओं और अन्य छात्रों के साथ समान रूप से रखे गए ओ. सी. आई. कार्डधारकों को छोड़कर, उद्देश्य के बिना

एक के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। जैसा कि इस आदेश के दौरान पहले ध्यान दिया गया था, ओ. सी. आई. कार्डधारकों को एनआरआई के साथ समानता में जो अधिकार दिया गया था, वह अन्य सभी समान उम्मीदवारों यानी भारतीय नागरिकों के साथ प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होना था। ऐसी स्थिति में जहां यह प्रदर्शित किया गया है कि याची संख्या 1 का जन्म वर्ष 2003 में हुआ है, वह 2006 से भारत में रह रही है और उसने भारत में अपनी शिक्षा प्राप्त की है, ऐसी छात्रा जिसने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए

भारत के नागरिक किसी भी अन्य छात्र की तरह ही 'लाभ' और 'नुकसान', पूर्व-चिकित्सा प्रवेश परीक्षा या ऐसी अन्य प्रवेश परीक्षा में भागीदारी समान होगी और याची संख्या 1 को इससे बड़ा कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वह कैलिफोर्निया, यू. एस. ए. में पैदा हुई थी। इसलिए, जो अधिकार प्रदान किया गया था और अस्तित्व में था, उसने भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं किया था ताकि ऐसे सभी अधिकारों को अचानक अस्वीकार कर दिया जा सके। अधिकार केवल प्रतिस्पर्धा करने का था। अगर यह संप्रभु राज्य की नीति होती तो इसे भविष्य के लिए विनियमित किया जा सकता था। जिस तरह से यह किया गया है, उससे इन सभी पहलुओं में जाने का कोई विचार स्पष्ट नहीं है।

55. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिस उद्देश्य के साथ अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया था ताकि भारत के प्रवासी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जा सके और उस संदर्भ में जब ओ. सी. आई. कार्डधारकों को समय-समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से अधिकार दिए गए थे, जिसके आधार पर ओ. सी. आई. कार्डधारकों ने इसे अपनाया था और भविष्य के लिए खुद को स्थापित करने के लिए काम किया था, तो इस तरह की प्रक्रिया में अर्जित अधिकार को वर्तमान तरीके से नहीं लिया जा सकता था, जो एक 'पूर्वव्यापी' अधिसूचना के रूप में कार्य करेगा। इसलिए, हालांकि अधिसूचना पूर्व-प्रत्यक्ष पूर्वव्यापी संचालन को निर्दिष्ट नहीं करती है, क्योंकि यह उपलब्ध अधिकारों को पूर्वव्यापी रूप से नष्ट कर देती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकार के ऐसे लाभार्थियों को इस तरह की अधिसूचना द्वारा प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि पूर्वव्यापी निर्माण के विरुद्ध नियम केवल इसलिए कानूनों पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकता का एक हिस्सा इसके पारित होने के पूर्व से लिया गया है, तत्काल मामले में अधिकार अधिसूचना के तहत प्रदान किए गए थे और ऐसे अधिकार बाद की अधिसूचना द्वारा लागू किए जा रहे हैं, जो हानिकारक है और इससे उस हद तक बचा जाना चाहिए और ऐसी पूर्व सक्रियता के बिना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

56. हम ध्यान देते हैं कि यह पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह उन ओसीआई कार्डधारकों को प्रभावित नहीं करता है जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, एक सीट हासिल की है और या तो एमबीबीएस पाठ्यक्रम या इस तरह के अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम से गुजर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं। हालांकि, यह उन व्यक्तियों के अधिकार से वंचित करने के लिए पूर्वव्यापी कार्रवाई के रूप में

कार्य करेगा जिनके पास ऐसा अधिकार था जो उस हद तक टिकाऊ नहीं है। खेल समाप्त होने पर गोल पोस्ट को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसलिए हमारा विचार है कि पूर्वगामी 955

पलावी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 956 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

पूर्वव्यापी परिणामों के परिणामस्वरूप होने वाले ऑपरेशन को अपास्त करना जाना चाहिए और ऐसे प्रतिकूल परिणामों से बचा जाना चाहिए।

57. अतः सम्मिलित मुद्दे की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, संक्षेप में, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि यद्यपि दिनांकित (आई. डी. 1) की आक्षेपित अधिसूचना एक नीति पर आधारित है और एक संप्रभु राज्य की वैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है, उसमें निहित प्रावधान केवल उन व्यक्तियों पर संभावित रूप से लागू होंगे जो (आई. डी. 1) के बाद किसी विदेशी देश में पैदा हुए हैं, यानी अधिसूचना की तारीख और जो उस तारीख से ओ. सी. आई. कार्डधारक के रूप में पंजीकरण चाहते हैं, क्योंकि उस समय माता-पिता के पास या तो वंश द्वारा नागरिकता लेने या संप्रभु राज्य की मौजूदा नीति की पृष्ठभूमि में एक विदेशी के रूप में बने रहने का विकल्प होगा।

58. उपरोक्त के आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि संप्रभु राज्य की नीति को आगे बढ़ाने में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत विचार किए गए उचित अधिसूचना पारित करने की शक्ति है, जिसमें दिए गए अधिकारों को प्रदान करने या बदलने की शक्ति है। हालांकि, जब किसी प्रदत्त अधिकार को वापस लिया जाता है, संशोधित किया जाता है या बदला जाता है, तो उसके लिए अग्रणी प्रक्रिया को दिमाग के अनुप्रयोग, इस तरह की वापसी या संशोधन के उद्देश्य के साथ संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए और ऐसा कोई भी निर्णय मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए। उस पृष्ठभूमि में, अधिनियम, 1955 की धारा 7 बी (1) के तहत सक्षम होने के बावजूद और संभावित होने के बावजूद, विवादित अधिसूचना वास्तव में उन अधिकारों को छीन रही है जो संप्रभु राज्य की नीति के रूप में भी प्रदान किए गए थे।

59. इसलिए, अधिसूचना संभावित रूप से टिकाऊ होने के कारण, हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि अधिसूचना का विवादित हिस्सा जो दिनांकित अधिसूचना संख्या

11.04.2005, 05.01.2007 और 05.01.2009 और खंड 4 (ii), इसके परंतुक और स्पष्टीकरण (1) को हटाने का परंतुक करता है, उन ओसीआई कार्डधारकों के संबंध में संभावित रूप से काम करेगा जिन्होंने इसे 04.03.2021 के बाद प्राप्त किया है।

60. हम आगे यह मानते हैं कि इन सभी मामलों में याचिकाकर्ता और अन्य सभी समान रूप से रखे गए ओ. सी. आई. कार्डधारक उन अधिकारों और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जो उन्हें पहले दिनांकित अधिसूचना 04.03.2021 में प्रदान किए गए थे और इसके बावजूद वे इसका लाभ उठा सकते हैं।

दिनांकित 04.03.2021 अधिसूचना में उत्कीर्ण बहिष्करण।चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं और इसी तरह से रखे गए ओ. सी. आई. कार्डधारकों की भागीदारी और इसमें या कहीं और पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर बाद की कार्रवाई नियमित होगी।”

16. यह स्पष्ट है कि निर्णय में कहा गया है कि अधिसूचना (दिनांक 04.03.2021) मनमाने ढंग से संचालित होती है क्योंकि पहली बार यह उपार्जित अधिकारों को न बचाने में दिमाग का उपयोग न करने का संकेत देता है। 04.03.2021 की अधिसूचना के खंड 4 (ii) पर परंतुक के आवेदन को प्राप्त करने के लिए वांछित उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं माना गया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो लोग 2005 से पहले पैदा हुए हैं और भारत में रह रहे हैं, उन्होंने भारत में अपनी शिक्षा प्राप्त की है और भारत के नागरिक अन्य बच्चों की तरह कुछ फायदे और नुकसान हुए हैं, और उन्हें एन. ई. ई. टी. परीक्षाओं या ऐसी ही परीक्षाओं में भाग लेने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह भी माना गया कि ऐसे वर्ग के लोगों को केवल इसलिए कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया गया क्योंकि वे विदेश में पैदा हुए थे और महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने उस संशोधन पर ध्यान दिया जिसने ओ. सी. आई. कार्ड धारकों को रियायत दी थी। इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जब प्रदत्त अधिकार को वापस ले लिया गया था और परिवर्तित किया गया था, तो इस तरह के परिवर्तन की प्रक्रिया में, इस तरह के वापसी या संशोधन के उद्देश्य के लिए दिमाग के अनुप्रयोग, संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए और ऐसा कोई भी निर्णय मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए। इस निष्कर्ष के आलोक में, न्यायालय ने माना कि अधिसूचना मन के गैर-अनुप्रयोग के दुष्प्रभाव से बचाती है और वास्तव में पूर्वव्यापी थी। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल वे व्यक्ति जिन्होंने 04.03.2021 के बाद ओ. सी. आई. कार्ड प्राप्त किए थे, उन्हें अधिसूचना के संदर्भ में अयोग्य घोषित किया गया था।

17. वर्तमान मामले में, हालांकि ओ. सी. आई. कार्ड याची द्वारा 04.08.2022 पर निर्भर था, यह तथ्य कि उसे वास्तव में 02.11.2015 पर पहले ओ. सी. आई. पंजीकरण कार्ड जारी किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की अनुष्का (उपरोक्त) के फैसले के संदर्भ में ओ. सी. आई. कार्ड धारक के लाभ का दावा करने की पात्रता निर्विवाद है। इस स्तर पर उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति, यानी 19.06.2023 पर, कानून में समर्थन योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप उन्हें एम्स और सभी भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा पीजी मेडिकल सीटों के लिए शेष परामर्श दौर में विचार करने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विचार उन सीटों के संबंध में होगा जो इस निर्णय की तारीख को अयोग्य हैं, चाहे वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित हों और जैसे कि विशेष रूप से भूतानी उम्मीदवारों आदि के लिए निर्धारित हों, यदि उन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

पलावी बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उनके जैसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा। इसके अलावा, यह सुविधा याची के साथ-साथ अन्य उम्मीदवारों के लिए भी खुली होनी चाहिए, जो 04.03.2021 से पहले जारी किए गए ओ. सी. आई. कार्डों के उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर और जो एन. ई. ई. टी. परीक्षा में अपने प्रदर्शन और उनकी रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह के परामर्श में भाग ले सकते हैं।

18. रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है और लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

लिखित याचिका की अनुमति दी गई।

निधि जैन